iihs®
INDIAN INSTITUTE FOR
HUMAN SETTLEMENTS

लॉकडाउन कहाँ और कब हटाना है, सामान्य स्थिति की ओर संक्रमण (ट्रांजिशन) को सक्षम करने के लिए क्या करें?

अरोमर रेवी, निदेशक, आईआईएचएस | 11 अप्रैल 2020

खंड I: लॉकडाउन कहाँ और कब उठाना है कैसे तय करें?

राष्ट्रीय-व्यापी लॉकडाउन से संक्रमण (ट्रांजिशन) में दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं संबोधित करने के लिए:

- किन स्थानों में लॉकडाउन को बनाए रखना /कहाँ से हटाना शुरू करना है और किन परिस्थितियों के तहत? (नीचे देखें)
- इन स्थानों के भीतर, कौन सी प्राथमिकता वाली गतिविधियाँ लॉकडाउन को कम कर सकती हैं और चरणबद्ध तरीके से सामान्य स्थिति को बहाल कर सकती हैं? (खंड II से IV देखें)

भारत से और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी आपातकालीन और आपदा जोखिम में कमी कार्यक्रमों से संकेत मिलता है कि साक्ष्य-आधारित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यह तय करने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किन स्थानों से लॉकडाउन उठाने की शुरुआत की जाए। यह लॉकडाउन को संभावित रूप से फिर से शुरू करने के निर्णय में भी सहायता कर सकता है - चूंकि महामारी उन स्थानों पर फिर से आ सकती है जहाँ यह नियंत्रित दिखाई दे रही है।

समग्र COVID-19 जोखिम सूचकांक

महामारी के इस रूप के लिए ऐसा करने का कोई सही और सिद्ध साधन नहीं है, लेकिन एक साधारण जीआईएस-आधारित सामान्यीकृत अभारित **संयोजित COVID-19 जोखिम सूचकांक** का निर्माण और दैनिक अपडेट शायद एक उपयोगी तरीका हो सकता है। शुरू में अनुमानित जनगणना 2011 के डेटा का उपयोग करके इसका अनुमान लगाया जा सकता है और बेहतर डेटा उपलब्ध होने के साथ इसमें सुधार किया जा सकता है। इस सूचकांक का पहला क्रम अनुमानित प्रॉक्सी संकेतकों का उपयोग कर सकता है, जो संभावित जोखिम और कमज़ोरियाँ के दो उप-सूचकांक बनाने के लिए ज्ञात जोखिम कारकों के आधार पर:

1. जोखिम (एक्सपोजर) सूचकांक

क. जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति[1]/ वर्ग किमी)
ख. शहरीकरण (% शहरी जनसंख्या[1])
ग. अलगाव या संगरोध में संभावित COVID -19 केस (अनुमानित केस/ मिलियन जनसंख्या[1])
घ. COVID-19 + पक्के केस (रिपोर्ट किए गए केस / मिलियन जनसंख्या[1])
ङ. COVID-19 से संबंधित मौतें (मृत्यु / मिलियन जनसंख्या[1])

---

[1] 2011 की जनगणना से अनुमान लगाया गया

2. **अतिसंवेदनशीलता सूचकांक**
   क. 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाली जनसंख्या का % (जनसंख्या का%[1])
   ख. शिशु मृत्यु दर (नवीनतम एसआरएस अनुमानों से मृत्यु / 1000 जीवित जन्म[1])
   ग. बीपीएल जनसंख्या का % (जनसंख्या का %[1])
   घ. कुल श्रमिकों में प्रवासियों का % (जनसंख्या का %[1])

जिलों / स्थानों का वर्गीकरण और संक्रमण (ट्रांजिशन) की रणनीतियां

जिलों / स्थानों को फिर तीन जोखिमों और अतिसंवेदनशीलता स्तरों (निम्न, मध्यम और उच्च) में से प्रत्येक में नौ जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो तालिका 3 में दिखाए गए अनुसार संभावित लॉकडाउन ट्रांजिशन रणनीति को निर्धारित करने में मदद करेगा, जो केवल उदाहरण के लिए है। **प्रत्येक स्तर को सरकार के बीच उपलब्ध आंकड़ों और परामर्श के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। और यह आंकड़े प्रत्येक श्रेणी और उचित ट्रांजिशन रणनीतियों के निर्धारण के आधार पर, जिलों और यूएलबी के अनुभवों के आधार पर होंगे।**

तालिका I: संयोजित COVID-19 जोखिम सूचकांक और संक्रमण रणनीतियों द्वारा जिलों / स्थानों का सांकेतिक वर्गीकरण

कमज़ोरियाँ सूचकांक	उच्च	बेहतर निगरानी के साथ चरणबद्ध मंदी (स्लोडाउन) पर विचार करें	लॉकडाउन बनाए रखें	लॉकडाउन बनाए रखें
	मध्यम	बेहतर निगरानी के साथ मंदी (स्लोडाउन) पर विचार करें	बेहतर निगरानी के साथ चरणबद्ध मंदी (स्लोडाउन) पर विचार करें	लॉकडाउन बनाए रखें
	निम्न	बेहतर निगरानी के साथ बहाली पर विचार करें	बेहतर निगरानी के साथ मंदी (स्लोडाउन) पर विचार करें	बेहतर निगरानी के साथ चरणबद्ध मंदी (स्लोडाउन) पर विचार करें
		निम्न	मध्यम	उच्च
		जोखिम सूचकांक		

COVID-19 जोखिमों को संबोधित करने ले लिए थोड़े समय के लिए अतिसंवेदनशीलता को कम करने में सीमित क्षमता है, प्रवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप, गरीबी को कम करने, आजीविका सुरक्षा और स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में वृद्धि को छोड़कर। इसलिए, COVID-19 के एक्सपोज़र और ट्रांसमिशन में कमी से सबसे प्रभावी तत्काल हस्तक्षेप होने की उम्मीद की जा सकती है। मध्यम-अवधि में, सामाजिक-आर्थिक कारकों में, विशेष रूप से अतिसंवेदनशीलता के निर्धारकों से जोखिम को प्रेरित करने की अपेक्षा की जाती है। **इसलिए, राष्ट्रीय बहाली और पुनर्निर्माण योजना और वित्तपोषण पैकेज के निर्माण के लिए मध्यम-अवधि की राज्य और जिला बहाली रणनीतियाँ आवश्यक होंगी।**

जोखिम और कमज़ोरियाँ की निगरानी करना

जोखिम और अतिसंवेदनशीलता की सरकार द्वारा दैनिक निगरानी (~ 725) जिलों में और 1 लाख से अधिक आबादी के सभी (~ 500) शहरी केंद्रों के लिए तुरंत शुरू होनी चाहिए। एक सप्ताह के भीतर यह देश भर में ब्लॉक / शहरी वार्ड स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए और एक डैशबोर्ड में निर्मित किया जाना चाहिए जिसे संबंधित सार्वजनिक एजेंसियों के साथ साझा किया जा सके। दूसरे सप्ताह में, राज्यों और जिलों के उन्नत निगरानी डेटा (लगभग सभी 6.5 लाख) गांवों और पड़ोस (देश के 8,000 शहरी केंद्रों) में उपलब्ध होने चाहिए।

प्रतिक्रिया क्षमता

जोखिम और अतिसंवेदनशीलता की कमी गंभीर रूप से इस बात से निर्धारित होती है कि भारत कितनी तेजी से आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों जोखिमों को दूर करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया क्षमता का विस्तार और उसे मज़बूत कर सकता है। इसे नीचे दिए गए अनुसार विस्तृत आर्थिक और स्वास्थ्य संकट के लिए पूर्व-प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करने और योजना बनाने के लिए **प्रतिक्रिया क्षमता** के सांकेतिक बहुआयामी **सूचकांक** का निर्माण करके भी देखा जा सकता है। इस सूचकांक के चारों ओर कार्यवाही में सुधार से समय के साथ एक्सपोजर इंडेक्स में कमी आ सकती है।

प्रतिक्रिया क्षमता सूचकांक

क. स्वास्थ्य देखभाल (हेल्थकेयर) पेशेवरों की उपलब्धता (डॉक्टर / मिलियन जनसंख्या[1])
ख. उपलब्ध सार्वजनिक + निजी अस्पताल के बिस्तर (बेड / मिलियन जनसंख्या[1])
ग. COVID-19 के लिए किए गए परीक्षण (रिपोर्ट किए गए परीक्षण / मिलियन जनसंख्या[1])
घ. सार्वजनिक + निजी अस्पताल में वेंटिलेटर (रिपोर्ट किए गए वेंटिलेटर / मिलियन जनसंख्या[1])
ङ. पीडीएस आपूर्ति की प्रति व्यक्ति रिलीज़ (प्रति व्यक्ति कैलोरी के बराबर)
च. प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष नकद-अंतरण (रु./ जनसंख्या[1])

खंड II : स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान लॉकडाउन के बाद ट्रांजिशन के लिए आवश्यक कार्य

सभी आठ क्षेत्रों में, **तीन महत्वपूर्ण समूहों** (वित्त और बैंकिंग, स्वास्थ्य प्रणाली और लाल रंग में बुनियादी सेवाएं) और **10 अतिरिक्त प्राथमिक** (लाल में) **गतिविधियों को प्राथमिकता** दी जाये। *भौगोलिक एकाग्रता, अनुक्रमण,* और गतिविधियों के कार्यान्वयन की *गति* को नियोजित किया जाये - भारत सरकार की अगुवाई वाली और राज्य सरकार की अगुवाई वाली नीतियों के मिश्रण के आधार, जो **लॉकडाउन** से लेकर **धीमी गति** से लेकर **बहाली** से लेकर **सेवाओं की मजबूती** और **विस्तार तक ट्रांजिशन** को परिभाषित करेंगी, जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है। इन गतिविधियों का विस्तृत विवरण, गैर-स्वास्थ्य सिस्टम हस्तक्षेप पर फोकस के साथ खंड III में दिया गया है।

I. प्रशासन और समन्वय

क. कानून और व्यवस्था को मज़बूत करना
ख. राज्य और जिला आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना
ग. राज्य और जिला प्रशासन और विकास गतिविधियों के कामकाज को बहाल करना
घ. आपतकालीन संचार और नागरिकों तक पहुँच को मजबूत करना
ङ. न्यायालयों और न्याय प्रणाली के कामकाज को बहाल करना

II. वित्त और बैंकिंग

क. बैंकिंग, डाकघर, एटीएम और ट्रेजरी सेवाओं को पुनर्स्थापित और विस्तारित करना
ख. राज्य सरकारों को विशेष राजकोषीय और वित्तीय पैकेज प्रदान और विस्तारित करना
ग. उद्यमों और किसानों के लिए ऋण समर्थन और ऋण पैकेज प्रदान और विस्तारित करना

III. स्वास्थ्य प्रणालियाँ

क. स्वास्थ्य निगरानी, विशेषकर COVID-19 स्क्रीनिंग, परीक्षण, अलगाव और संगरोध सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और विस्तार
ख. COVID-19 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और विस्तारित करना
ग. COVID-19 के जोखिम की संभवना वाले फ्रंटलाइन स्वास्थ्य और अन्य कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करना
घ. अन्य संक्रामक रोगों, एनसीडी और अन्य कमजोर आबादी को संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों के कार्यों को पुनर्स्थापित करें
ङ. फार्मा और चिकित्सा उपकरण आपूर्ति श्रृंखला की पुनर्स्थापना और विस्तार करना

IV. बुनियादी सेवाएँ

क. स्थिर विद्युत आपूर्ति बनाए रखना
ख. स्थिर ईंधन की आपूर्ति बनाए रखना
ग. आईसीटी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन
घ. स्थिर जल आपूर्ति सेवाओं को बनाए रखना
ङ. स्थिर स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट सेवाओं को बहाल करना

V. भूख, खाद्य सुरक्षा, कृषि, वानिकी और संबद्ध गतिविधियाँ

क. पीडीएस और वस्तु के रूप में समर्थन को मजबूत बनाना और विस्तार करना

ख. दूध, मांस, मछली, फल और सब्जियों के उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को पुनर्स्थापित करना

ग. कृषि आधारित गतिविधि और विशेषकर रबी की फसल का समर्थन करना

घ. कृषि मजदूर और कामगारों के सुरक्षित आवागमन को सक्षम करना

ङ. सिंचाई और कृषि सेवाएँ बहाल करना

च. एनटीएफ़पीएस और लकड़ी-आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला बहाल करना

VI. गरीबी, आजीविका और सामाजिक संरक्षण

क. डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, बढ़ाई गयी पेंशन, आय समर्थन का विस्तार और बेहतर बनाना

ख. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका गारंटी कार्यक्रमों का विस्तार और बेहतर बनाना

ग. मज़दूरों और विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों की और उनकी आजीविका की सुरक्षा

घ. प्रवासी श्रमिकों और प्रवासी परिवारों की जरूरतों को सुरक्षित और संबोधित करना

ङ. कमजोर समूहों की जरूरतों की रक्षा करना और उनका पता लगाना

VII. परिवहन प्रणालियाँ

क. रेल, ट्रक, वायु और पोत द्वारा माल परिवहन को बहाल और विस्तारित करना

ख. रेल, बस और नाव के द्वारा राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय यात्री परिवहन बहाल करना

ग. शहर के अंदर सार्वजनिक परिवहन (रेल, मेट्रो और बस) की बहाली और विस्तार करना

घ. शहर के अंदर निजी परिवहन बहाल करना

ङ. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री हवाई परिवहन बहाल करना

VIII. आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करना और बढ़ाना

क. आवश्यक सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल और बढ़ाना

ख. गोदामों और कोल्ड चेन सेवाओं को बहाल करना

ग. आवश्यक सामग्री और उत्पादों के उत्पादन का विस्तार करना

IX. निर्माण और आवास

क. निर्माण और आवास गतिविधि को पुनर्स्थापित और विस्तारित करना

X. शिक्षा प्रणाली

क. स्कूल और विश्वविद्यालय के कामकाज को पुनर्स्थापित करना

सारांश तालिका I: स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान लॉकडाउन से बाहर परिवर्तनकाल के लिए चालीस आवश्यक चीजें: सूचक वर्तमान स्थिति और संभावित परिवर्तनकाल परिदृश्य

क्र.सं.	प्राथमिकता वाली कार्यवाहियाँ	सूचक वर्तमान स्थिति		सूचक परिवर्तकाल परिदृश्य						
				भारत सरकार के नेतृत्व वाले				राज्य सरकार के नेतृत्व वाले		
		अखिल भारतीय	राज्य	I	II	III	IV	V	VI	VII
	प्रशासन और समन्वय									
1	कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
2	राज्य और जिला आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना	↗	↗	↗	↗	**↗**	↗	↗	↗	**↑**
3	राष्ट्रीय, राज्य और जिला प्रशासन और विकास गतिविधियों के कामकाज को बहाल करना	↓	↓	↓	↘	**→**		↓	↘	**→**
4	स्टेकहोल्डर और सिविल सोसायटी समन्वय स्थापित करना		↘					↘	→	→
5	आपतकालीन संचार और नागरिकों तक पहुँच को मजबूत करना	↗	→	↗	↗	**↗**	↗	→	↗	↑
6	न्यायालयों और न्याय प्रणाली के कामकाज को बहाल करना	↘	↘	↘	↘	**→**		↘	→	↗
	वित्त और बैंकिंग									
7	बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, एटीएम और ट्रेज़री सेवाओं को पुनर्स्थापित और विस्तारित करना	↘	↘	→	↗	**↗**		→	→	**↑**
8	राज्य सरकारों को विशेष राजकोषीय और वित्तीय पैकेज प्रदान और विस्तारित करना	↘		↗	↗	**↗**		↗	↗	**↑**
9	उद्यमों और किसानों के लिए ऋण और ऋण समर्थन पैकेज प्रदान और विस्तारित करें	↘		↗	↗	**↗**	→	↗	↗	**↑**
	स्वास्थ्य प्रणाली									
10	स्वास्थ्य निगरानी, विशेषकर COVID-19 स्क्रीनिंग, परीक्षण, अलगाव और संगरोध सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	↗	→	↗	↗	**↗**	↗	↗	↗	**↑**
11	COVID-19 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और विस्तारित करना		→					→	→	**↑**
12	COVID-19 के जोखिम की संभवना वाले फ्रंटलाइन स्वास्थ्य और अन्य कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करना		→					→	↗	**↗**
13	अन्य संक्रामक रोगों, एनसीडी और अन्य कमज़ोर आबादी को संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों के कार्यों को पुनर्स्थापित करें	↘	↘	↘	→	**↗**		↘	→	**↗**
14	फार्मा और चिकित्सा उपकरण आपूर्ति श्रृंखला की पुनर्स्थापना और विस्तार करना	↘	↘	→	→	**↗**		→	↗	**↗**
	बुनियादी सेवाएँ									
23	स्थिर विद्युत आपूर्ति बनाए रखना	↗	→	→	→	→		→	→	↗
24	स्थिर ईंधन आपूर्ति बनाए रखना	↗	→	→	→	→		→	→	↗
25	आईसीटी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन	↗	↗	↗	↗	**↗**		↗	↗	**↑**
26	स्थिर जल आपूर्ति सेवाओं को बनाए रखना		→					→	→	→
27	स्थिर स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट सेवाओं को बहाल करना		↘					↘	→	**↗**
	भूख, खाद्य सुरक्षा, कृषि, वानिकी और संबद्ध गतिविधियाँ									
15	पीडीएस और वस्तु के रूप में समर्थन को मज़बूत बनाना और विस्तार करना	→	→	↗	↗	**↗**		↗	↗	**↑**
16	दूध, मांस, मछली, फल और सब्जियों के उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को पुनर्स्थापित करें	↘	↘	→	↗	↗		→	→	↗
17	कृषि आधारित गतिविधि और विशेषकर रबी की फसल का समर्थन करना	→	→	↗	↗	**↗**		↗	↗	**↗**
18	कृषि मजदूर और कामगारों के सुरक्षित आवागमन को सक्षम करना	→	→	↗	↗	↗		↗	↗	↗
19	सिंचाई और कृषि सेवाएँ बहाल करना	→	→	→	→	→		→	→	→
20	एनटीएफ़पीएस और लकड़ी-आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला बहाल करें	↓	↓	↓	↘	→		↓	↘	→
	गरीबी, आजीविका और सामाजिक संरक्षण									
18	डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, बढ़ाई गयी पेंशन, आय समर्थन का विस्तार और बेहतर बनाना	→	→	↗	↗	**↗**		↗	↗	**↑**
19	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका गारंटी कार्यक्रमों का विस्तार और बेहतर बनाना	→	→	↗	↗	↗		↗	↗	↑
20	मज़दूरों और विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों की और उनकी आजीविका की सुरक्षा	↓	↓	→	→	**↗**		→	→	**↗**
21	प्रवासी श्रमिकों और प्रवासी परिवारों की जरूरतों को सुरक्षित और संबोधित करना	↓	↓	→	→	↗		→	→	↗
22	कमज़ोर समूहों की जरूरतों की रक्षा करना और उनका पता लगाना	↓	↓	→	→	↗		→	→	↗
	परिवहन प्रणाली									
28	रेल, ट्रक, वायु और पोत द्वारा माल परिवहन को बहाल और विस्तारित करना	↘	↘	→	→	**↗**	↗	↘	→	**↗**
29	रेल, बस और नाव के द्वारा राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय यात्री परिवहन बहाल करना	↓	↓	↓	↘	**→**		↓	→	**↗**
30	शहर के अंदर (इंट्रासिटी) सार्वजनिक परिवहन (रेल, मेट्रो और बस) की पुनर्स्थापना और विस्तार करना		↓	↓	↘	→		↓	→	↗
31	शहर के अंदर (इंट्रासिटी) निजी परिवहन बहाल करना		↓	↓	↓	→		↓	↘	↗
32	घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री हवाई परिवहन बहाल करना	↓		↓	↓	→	**↗**			
	आपूर्ति श्रृंखला									
34	आवश्यक सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्स्थापित और विस्तारित करना		↘					→	↗	**↑**
33	गोदामों और कोल्ड चेन सेवाओं को पुनर्स्थापित करना		↘					↘	→	↗
35	आवश्यक सामग्री और उत्पादों के उत्पादन का विस्तार करना	→	↘	↗	↗	↗		→	↗	↑
	निर्माण और आवास									
39	निर्माण और आवास गतिविधि को पुनर्स्थापित और विस्तारित करना	↓	↓	↓	↘	↗		↓	↘	↗
	शिक्षा प्रणालियाँ									
40	स्कूल और विश्वविद्यालय के कामकाज को पुनर्स्थापित करना	↓	↓	↓		→		↓	↘	↗

	लेजेंड: परिवर्तनकाल परिदृश्य	परिवर्तनकाल लेजेंड	
I	समय की एक विस्तारित अवधि के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन की निरंतरता (आर्थिक गतिविधि के अपवादों के विस्तार के साथ)	सुदृढ़ीकरण और विस्तार करना	↑
II	यात्री और माल यातायात के अंतरराज्यीय गतिशीलता का आंशिक लॉकडाउन (आर्थिक गतिविधि के अपवादों के विस्तार के साथ)	बहाली	↗
III	सभी अंतरराज्यीय यात्री और माल यातायात की राष्ट्रव्यापी बहाली	बनाए रखें और सुरक्षित रखें	→
IV	चरणों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को फिर से शुरू करना	गति कम करना	↘
V	एक विस्तारित अवधि के लिए (आर्थिक गतिविधि के अपवादों के विस्तार के साथ) विशेष राज्य / जिलों का निरंतर लॉकडाउन	लॉक डाउन	↓
VI	विशेष राज्य / जिले के यात्री और माल यातायात का लॉकडाउन (आर्थिक गतिविधि के अपवादों के विस्तार के साथ) आंशिक लॉकडाउन		
VII	यात्री और माल यातायात का राज्य-व्यापी पुनः आरंभ		

प्राथमिकता जांच सूची/चेकलिस्ट: स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान लॉकडाउन के बाद ट्रांजिशन के लिए समर्थन देने वाले कार्य

यह सतत स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था, अवसंरचना और प्रशासन के आंशिक या पूर्ण ट्रांजिशन के दौरान राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने के लिए प्रमुख मुद्दों की एक व्यापक सूची है। इसमें विकल्पों का एक उपयुक्त संयोजन, उनकी भौगोलिक कवरेज, अनुक्रमण और कार्यान्वयन की गति का चयन करने के लिए राज्य और स्थानीय निर्णयों का एक जटिल समूह शामिल होगा। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जिले के भीतर और एक राज्य में जिलों के बीच गतिशील तरीके से बदल सकता है।

इस ट्रांजिशन को विकेन्द्रीकृत और प्रत्यायोजित प्रतिक्रिया योजना, ट्रैकिंग और कार्यान्वयन की आवश्यकता है, जो COVID-19 प्रकोप के विस्तार द्वारा लगाए गए दबाव और भारत सरकार के मार्गदर्शन, हस्तक्षेप और वित्तीय और विकास सहायता पैकेज के अंदर राज्य और जिला प्रशासनों द्वारा सबसे बेहतर नियंत्रित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय संकट को सभी भारतीयों के लिए विकास के अवसर में बदलना

यह संकट केवल वस्तु के रूप में और नकद पात्रता और समर्थन के बारे में नए वैश्विक नवाचार करने का अवसर नहीं है, बल्कि मौजूदा राष्ट्रीय और राज्य विकास कार्यक्रमों और योजनाओं को युक्तिसंगत और समेकित करने का भी है। यह भारत की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचे और विकास प्रणालियों को बेहतर, अधिक प्रभावी ढंग से, साफ और हरा बनाने में मदद कर सकता है, जिससे जोखिम को कम करने और प्रणाली का लचीलापन बढ़ाया जा सकता है। गरीब, कुपोषित और भूखे, वृद्ध, निशक्त और जिनकी आजीविका ख़राब हो चुकी है या जोखिम बाधित है, उन पर विशेष फोकस केंद्रीय है - क्योंकि यह संभवतः सबसे बड़ा आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य विघटन है जिसे देश ने विभाजन के बाद अनुभव किया है।

एक्शन का सांकेतिक और उदाहरण सेट: प्रत्येक राज्य और जिले द्वारा नियमित रूप से पुनर्गणना की जानी चाहिए

कार्यवाहियों के निम्नलिखित सेट केवल सांकेतिक हैं और साक्ष्य और उपयुक्त जानकारी के आधार पर दैनिक और साप्ताहिक आधार पर जिला और राज्य स्तर पर जाँचे जाने की आवश्यकता होगी। यह कई राज्य सरकारों और जिला प्रशासकों के अनुरोध पर 29 मार्च 2020 को भेजी गयी आईआईएचएस परामर्शी से आगे बढ़ता है। यह व्यापक होने का प्रायस नहीं करता है, बल्कि कार्यान्वयन में सहायता के लिए हस्तक्षेपों को श्रेणियों में डालता है, और इसके भीतर तीन महत्वपूर्ण समूहों (वित्त और बैंकिंग, स्वास्थ्य प्रणाली और लाल रंग में बुनियादी सेवाएं) और गतिविधियों के अन्य 8 समूहों में 10 प्राथमिकता वाली (लाल रंग में) गतिविधियां देता है। यह उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा विशेष महामारी विज्ञान या स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित सलाह की जगह नहीं लेता है। पूरक

प्रश्नों का एक सेट जो कई प्रक्रियाओं की जांच करता है जिनकी आवश्यकता ट्रांजिशन की तैयारी करने के लिए की हो सकती है, उसे खंड 2 में सूचीबद्ध किया गया है।

सारांश तालिका 1 लॉकडाउन के मध्य में, देश की वर्तमान स्थिति का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक समकालिक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। फिर यह एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो वर्तमान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर चरणबद्ध ट्रांजिशन को सक्षम करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियों के समन्वित सेट का विश्लेषण और प्राथमिकता देने में सक्षम होता है। देशव्यापी लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति से पाँच बदलाव (और तालिका 1 में इस्तेमाल किए गए प्रतीकों को नीचे बॉक्स 1 में दिखाया गया है)

बॉक्स 1: Covid - 19 के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से सामान्य की बहाली के लिए पांच ट्रांजिशनस

1. लॉकडाउन [सेवाओ का] ⬇
2. मंदी [सेवाओं की] ⬊
3. [पूरव-लॉकडाउन सेवा की सृथतिि] बनाए और सुरकृषति रखना ➡
4. बहाली [सेवाओं की] ⬈
5. [सेवाओं] को मजबूत और वसि्तारति करना ⬆

सारांश तालिका कैसे पढ़ें

सारांश तालिका गतिविधि के दस समूहों में 40 संभावित कार्यवाहियों को सूचीबद्ध करती है। उनके भीतर तीन समूहों (वित्त और बैंकिंग, स्वास्थ्य प्रणाली और लाल रंग में बुनियादी सेवाओं) को आम तौर पर सभी गतिविधियों पर प्राथमिकता कार्यवाही की आवश्यकता होगी। राज्यों और जिला अधिकारियों को तत्काल प्राथमिकता के लिए न्यूनतम 10 प्राथमिकता वाली गतिविधियों (लाल में) पर विचार करना चाहिए, जिसके बाद अन्य कम महत्वपूर्ण गतिविधियों, जैसे जमीन पर स्थिति के आधार पर स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खोलना या निर्माण कार्य फिर से शुरू करने पर विचार किया जा सकता है।

राज्य और जिला स्तर पर, 15 अप्रैल, 2020 के बाद कार्यान्वयन विकल्पों की एक सीमा का पता लगाने के लिए सात सांकेतिक ट्रांजिशन परिदृश्यों का एक सेट बनाया गया है। ये ट्रांजिशन परिदृश्य विकल्पों की निरंतरता (लॉकडाउन की निरंतरता से लेकर सभी आवागमन और आर्थिक गतिविधियाँ खुलने तक) प्रस्तुत करते हैं। जिसके भीतर भौगोलिक अनुप्रयोग (पड़ोस, गाँव, वार्ड, ब्लॉक, जिला या पूरे राज्य), क्रमबद्धता और ट्रांजिशन की गति को जांचा जा सकता है।

बॉक्स 2: भारत सरकार और राज्य सरकार की नीति में परिवर्तन के सात परिदृश्य

भारत सरकार में परिवर्तन के चार संभावित परिदृश्य की और राज्य सरकार की नीतियों में तीन परिवर्तन, नीचे दिखाए गए हैं।

भारत सरकार के नेतृत्व वाली नीतियों और हस्तक्षेपों में परिवर्तन

I. **समय की विस्तारित अवधि के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन की निरंतरता:** आर्थिक गतिविधि के अपवादों के विस्तार के साथ[2]

II. **यात्री और माल यातायात के अंतरराज्यीय आवाजाही का आंशिक लॉकडाउन**[3]: आर्थिक गतिविधि के अपवाद के विस्तार के साथ

III. **सभी अंतरराज्यीय यात्री और माल यातायात की राष्ट्रव्यापी बहाली**

IV. **अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की चरणबद्ध बहाली**[4]

राज्य सरकार के नेतृत्व वाली नीतियों और हस्तक्षेपों में परिवर्तन

I. **समय की एक विस्तारित अवधि के लिए विशेष राज्य / जिलों की लॉकडाउन की निरंतरता**: आर्थिक गतिविधि के अपवादों के विस्तार के साथ

II. **विशेष राज्य / जिलों के यात्री और माल यातायात का आंशिक लॉकडाउन:** आर्थिक गतिविधि के अपवादों के विस्तार के साथ

III. **यात्री और माल यातायात की राज्यव्यापी बहाली**

स्वास्थ्य प्रभाव और जोखिम और आर्थिक और आजीविका जोखिम के बारे में सबसे अच्छी उपलब्ध जानकारी के आधार पर, राज्यों और अन्य प्रमुख हितधारकों (जैसे रेलवे, एयरलाइंस और पोर्ट) के परामर्श से भारत सरकार, सांकेतिक परिदृश्य I से IV तक रोल-आउट पर एक नीतिगत निर्णय लेगी। *यह ध्यान देने के बात है, यह अकल्पनीय नहीं है, कि यदि COVID-19 स्थिति खतरनाक रूप से बिगड़ती है, तो चुनिन्दा या देशव्यापी लॉकडाउन में रोल-बैक संभव है।*

प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य सरकार को जिला प्रशासन, प्रमुख हितधारकों और नागरिकों के परामर्श से परिदृश्य V से VII पर अगुवाई करनी चाहिए, जो संबंधित ब्लॉकों / शहरी क्षेत्रों और जिलों में परिचालन स्थिति पर प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य, आर्थिक और आजीविका जोखिमों पर सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी देगा। यह अनुमान है कि 21-दिवसीय लॉकडाउन लगभग वास्तविक समय डेटा और निगरानी प्रणालियों को सक्षम करेगा, जो अगले कुछ महीनों में लगातार बेहतर होगा।

चालीस प्राथमिकता वाले कार्यों में से प्रत्येक का गुणात्मक रूप से राज्य सरकारों के लिए इसकी वर्तमान स्थिति पर और क्षेत्राधिकार (जैसे कि केंद्र के साथ नागरिक उड्डयन) भारत सरकार, दोनों के आधार पर

---

[2] विशेष रूप से आवश्यक आर्थिक गतिविधियाँ (जैसे कृषि, मत्स्य पालन)

[3] रेल और / या सड़क और / या हवा और / या नाव / जहाज द्वारा

[4] नामित बंदरगाहों, हवाई अड्डों और संभावित भूमि सीमाओं से

मूल्यांकन किया गया है। सिद्धांत रूप में, संकेतकों के उचित रूप से चुने गए सेट के साथ उसी सेट का बड़े पैमाने पर प्रत्येक जिले या राज्य के लिए निर्माण किया जा सकता है।

प्राथमिकता वाली कार्यवाहियों का एक सेट, उनका अनुक्रमण, समय और निष्पादन को एक अधिक लचीली (रिजिलिअंट) और सुरक्षित पोस्ट-लॉकडाउन स्थिति में पूर्ण संक्रमण (ट्रांजिशन) को ट्रैक करने के लिए की गति को निर्धारित, नियोजित, कार्यान्वित और मॉनिटर किया जा सकता है।

खंड III: एक लॉकडाउन से बाहर ट्रांजिशन में करने के लिए चालीस आवश्यक कार्य

I. प्रशासन और समन्वय

1. **कानून और व्यवस्था को मज़बूत बनाना:** स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सुरक्षा के साथ-साथ, बीमार, बुजुर्ग, गरीब, कमजोर, प्रवासियों और विस्थापितों को लॉकडाउन और ट्रांजिशन उपायों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना; रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ। क्षेत्र संगरोध (क्वारेन्टाइन) और अलगाव के समर्थन की मांग में ट्रांजिशन के बाद वृद्धि के लिए तैयारी; अपराध, एकत्रीकरण, यातायात और भीड़ प्रबंधन को संबोधित करने के लिए।
2. **राज्य और जिला आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को मज़बूत करना:** उन्हें आवश्यक सेवाओं को चालू रखने और बहाली के लिए तैयार करने के लिए लाइन/संबन्धित विभागों के प्रमुख कर्मियों के साथ स्टाफ देना। हॉट स्पॉट और अड़चनों को ट्रैक करने के लिए जीआईएस और विश्लेषणात्मक क्षमता स्थापित करना, सोशल और प्रसारण मीडिया के लिए आपातकालीन संचार क्षमता स्थापित करना। नागरिक, हितधारक और फ्रंटलाइन स्टाफ से प्रश्नों का जवाब देने और अड़चनों की पहचान करने के लिए समर्थन हॉटलाइन और कॉल सेंटर से सूचना प्रवाह को सक्षम करना।

3. **राष्ट्रीय, राज्य और जिला प्रशासन और विकास गतिविधियों के कामकाज को बहाल करना:** प्राथमिकता वाले विभागों और कार्यों के साथ, जिला और राज्य प्रशासन के सामान्य कामकाज की चरणबद्ध बहाली। ट्रांजिशन के बाद के कार्य भार में वृद्धि के लिए तैयार करने के लिए लॉकडाउन के दौरान सक्रिय फ्रंटलाइन कर्मचारियों की छुट्टियों के रोटेशन पर विचार किया जाना चाहिए।

4. **स्टेकहोल्डर और सिविल सोसाइटी समन्वय स्थापित करना:** Covid-19 और पोस्ट-लॉकडाउन स्थानीय आर्थिक और आजीविका बहाली को संबोधित करने के लिए सविनय समाज और प्रमुख हितधारकों के प्रभावी समन्वय को सक्षम करने के लिए पंजीकरण और मान्यता और साप्ताहिक समीक्षा बैठकों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से।

5. **आपतकालीन संचार और नागरिकों तक पहुँच को मज़बूत करना:** इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी के आधार पर सोशल, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दैनिक / साप्ताहिक आपतकालीन संचार में सहायता के लिए पेशेवरों की एक स्वयंसेवी टीम की स्थापना करके। शिकायतों और सुझावों पर प्रतिबंध लगाने और अड़चनों को दूर करने के लिए कॉल सेंटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया समर्थन और विश्लेषण के साथ नागरिकों तक पहुँच तंत्र स्थापित करना।

6. **न्यायालयों और न्याय प्रणाली के कामकाज को बहाल करना:** संचरण के जोखिम को कम करने के लिए उचित दूरी के साथ, स्थानीय, जिला और उच्च न्यायालय के कामकाज और न्याय प्रणाली की चरणबद्ध बहाली।

II. वित्त और बैंकिंग

7. **बैंकिंग, डाकघर, एटीएम और ट्रेजरी सेवाओं को पुनर्स्थापित और विस्तारित करना:** प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, बढ़ी हुयी पेंशन आदि के वितरण और आवश्यक सेवाओं और सरकारी कामकाज को चालू रखने के लिए आवश्यक है। यदि स्थानीय नकद आपूर्ति कम बताई गई है, तो पुनःपूर्ति पर विचार करें यह अनौपचारि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। जिले / राज्य में रहने वाले सभी पात्र नागरिकों तक डिजिटल / विस्तारित वित्तीय समावेशन और पहुँच के विस्तार को सक्षम करने के लिए क्रॉस-फंक्शनल टास्क फोर्स की स्थापना करना। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और वितरण के कामकाज को ट्रैक करने के लिए सिस्टम स्थापित करना और अपेक्षित लीक को बंद करना।

8. **राज्य सरकारों को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान और विस्तारित करना:** भारत सरकार द्वारा मौजूदा स्थानान्तरण, केंद्रीय योजनाओं और सहायता के अलावा, राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए एक उपयुक्त मैक्रो-मौद्रिक और राजकोषीय पैकेज का निर्माण करना। राज्य सरकारों द्वारा विकास और नियामक हस्तक्षेपों के सरल सेट बदलना और बढ़ाना जो उभरती मुख्य चुनौतियों - जैसे भूख, आजीविका का नुकसान और बढ़ी हुई गरीबी और जोखिम, ऋण और ऋण पहुँच को गहरा करना, उद्यम दिवालिया, अटकलें और जमाखोरी - को संबोधित करे। मासिक समीक्षा और पुनर्गणना के साथ जिलेवार नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र।

9. **उद्यमों और किसानों के लिए ऋण समर्थन और क्रेडिट पैकेज प्रदान और विस्तारित करना:** भारत सरकार द्वारा उचित ऋण सहायता और ऋण वृद्धि पैकेज का निर्माण, किसानों, प्रवासियों, स्वयं-खाते, सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों, व्यापार, परिवहन, आतिथ्य, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत सेवाओं सहित गंभीर रूप से तनावग्रस्त क्षेत्रों और समूहों को संबोधित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाया और अनुकूलित किया जाना चाहिए। इसे डिजिटल / विस्तारित वित्तीय समावेशन के विस्तार के साथ लिंक करें।

III. स्वास्थ्य प्रणालियाँ

10. **स्वास्थ्य निगरानी, विशेषकर COVID-19 स्क्रीनिंग, परीक्षण, अलगाव और संगरोध सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और विस्तार:** व्यक्तिगत और निजी सुविधाओं का उपयोग करते हुए, अलगाव और संगरोध रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए व्यक्तिगत मामलों, समुदायों, पड़ोस और कस्बों / गांवों की निगरानी, अलगाव और संगरोध का तेजी से विस्तार करने के लिए, प्रकोप को सीमित करने और गंभीर मामलों में वृद्धि के दौरान अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर बोझ को कम करने के लिए।

11. **COVID-19 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और गंभीर देखभाल को मज़बूत और विस्तारित करना:** वर्तमान अवसंरचना और सेवाओं को मज़बूत करना और गंभीर मामलों, विशेष रूप से अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों के साथ, की अपेक्षित वृद्धि के लिए तैयारी करना। प्रकोप की बदलती तीव्रता और वितरण के आधार पर संभावित सेवा कवरेज की योजना बनाएं और लक्षित करें।

12. **COVID-19 के जोखिम की संभवना वाले फ्रंटलाइन स्वास्थ्य और अन्य कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करना:** निगरानी की निरंतरता और गंभीर देखभाल और आवश्यक चिकित्सा और स्वच्छता जैसी अन्य सेवाओं की प्रदानगी सुनिश्चित करना।

13. **अन्य संक्रामक रोगों, एनसीडी और अन्य कमजोर आबादी को संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों के कार्यों को पुनर्स्थापित करना:** प्रमुख गैर-संचारी (जैसे हृदय रोग) और संक्रामक रोगों (जैसे मलेरिया और टीबी) को संबोधित करने पर वापस लौटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करना। यह भारत में मृत्यु और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है।

14. **फार्मा और चिकित्सा उपकरण आपूर्ति श्रृंखला की पुनर्स्थापना और विस्तार करना**: व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), परीक्षण, गंभीर देखभाल के लिए चिकित्सा उपकरण, COVID-19 के लिए उचित चिकित्सा और दवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब वे अगले 12-18 महीनों में उपलब्ध हो जाएं, डबल्यूएचओ के अनुसार। अन्य संक्रामक रोगों और एनसीडी के लिए दवा और आपूर्ति भी।

IV. बुनियादी सेवाएँ

15. **स्थिर विद्युत आपूर्ति बनाए रखना:** उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को आपूर्ति की निर्बाध आवासीय और कृषि बिजली और तेजी से पोस्ट-लॉकडाउन बहाली सुनिश्चित करने के लिए वितरण अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना।

16. **ईंधन की आपूर्ति स्थिर बनाए रखना:** और माल परिवहन, आपातकालीन वाहनों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त स्टॉक (डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और सीएनजी के); महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए बैकअप या कैप्टिव बिजली की आपूर्ति (जैसे मोबाइल टॉवर, टेलीकॉम सिस्टम और डेटा सेंटर, अस्पताल); महत्वपूर्ण विनिर्माण सुविधाओं, गोदामों और कोल्ड चेन, कृषि और संबद्ध गतिविधि, और लॉक-डाउन केडी बाद सार्वजनिक और निजी यात्री मांग में वृद्धि के लिए तैयारी करना।

17. **आईसीटी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन:** फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी नागरिकों के लिए संपर्क (कनेक्टिविटी) सक्षम करने के लिए, और राज्य तथा स्थानीय प्रशासन के साथ एक खुला और पारदर्शी इंटरफ़ेस बनाना। निजी क्षेत्र के समर्थन के साथ संकटग्रस्त, अत्यधिक संवेदनशील और विशेष समूहों (जैसे प्रवासियों) में नागरिकों को जवाब देने के लिए हेल्पलाइन स्थापित करना। जहाँ उपयुक्त हो, शैक्षिक, लघु-स्तरीय सेवा और नागरिक समाज संस्थानों को ऑनलाइन सीखने, कौशल और व्यावसायिक विकास सक्षम करने के लिए डिजिटल सुविधा (एक्सेस) सक्षम करना।

18. **जल आपूर्ति सेवाओं को स्थिर बनाए रखना:** पानी से संबंधित बीमारियों के जोखिम को, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन परिस्थितियों में रहने वाली बड़ी आबादी में, सीमित करने के लिए। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में नियमित पाइपलाइन-आधारित या टैंकर की आपूर्ति। जहाँ आपूर्ति भूजल को पंप करने पर निर्भर करती है वहाँ बिजली की स्थिर आपूर्ति।

19. **स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट सेवाओं की स्थिर बहाली करना:** स्वच्छता की स्थिति को बनाए रखने और सुधारने के लिए, पोस्ट-लॉकडाउन उछाल की तैयारी में। लॉकडाउन का उपयोग स्रोत पर ठोस अपशिष्ट की छटनी और इसकी रीसाइक्लिंग बढ़ाने के लिए करें। COVID-19 के जोखिम वाले फ्रंटलाइन स्वच्छता कार्यकर्ताओं और ठोस अपशिष्ट कार्यकर्ताओं की बढ़ी हुई सुरक्षा।

V. भूख, खाद्य सुरक्षा, कृषि, वानिकी और संबद्ध गतिविधियाँ

20. **पीडीएस और वस्तु के रूप में समर्थन को मज़बूत बनाना और विस्तार करना**: स्टॉक की ट्रैकिंग सहित, रोज़ के आवागमन को सक्षम करना और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को वस्तु के रूप समर्थन (जैसे खाना, सिविल सप्लाई, केरोसीन और एलपीजी) की प्रदानगी के लिए आवश्यक है, जो इन प्रणालियों को चालू रखते हैं। आंगनवाड़ी और मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमों, अस्पतालों और महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और बुजुर्गों, कमज़ोर और दूरस्थ आबादी के लिए आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष देखभाल। पीडीएस आपूर्ति और चैनलों के लिए सार्वभौमिक पहुँच का विस्तार, जिसमें उन सभी परिवारों का आपातकालीन पंजीकरण शामिल है जिन्होंने आवेदन किया है और पीडीएस पहुँच के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

21. **दूध, मांस, मछली, फल और सब्जियों के उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को पुनर्स्थापित करना:** पोषण सुरक्षा, विशेषकर कमज़ोर और कुपोषित समूहों; मिड-डे मील और आपातकालीन भोजन कार्यक्रम के लिए सब्जियों और फलों, दूध, अंडे, मांस और मछली, उनके बाजारों, वितरण, ठंडे और खुदरा श्रृंखलाओं के लिए उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करने के लिए; उत्पादक समूहों और उद्यमों की पर्याप्त आय के साथ।

22. **कृषि आधारित गतिविधि और विशेषकर रबी की फसल का समर्थन करना**: अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली अपेक्षित बम्पर रबी फसल का समर्थन करने के लिए, जिसमें उपयुक्त एमएसपी हस्तक्षेप, प्राथमिक और माध्यमिक कृषि बाजारों का सामान्यीकरण और विस्तार और श्रमिकों और कृषि उपज का सुरक्षित आवागमन शामिल है।

23. **कृषि मज़दूर और कामगारों के सुरक्षित आवागमन को सक्षम करना**: सभी राज्यों में और राज्यों के अंदर फसल और कृषि कार्यों को सक्षम करने के लिए। रेल और बस दोनों के द्वारा बड़ी संख्या में श्रमिकों की सुरक्षित आवाजाही, जिसमें उपयुक्त शिक्षा, जांच, निगरानी, परीक्षण और अलगाव शामिल हैं यदि COVID-19 से संक्रमित हैं। इस पर अत्यधिक दबाव क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, भूख और कुपोषण पर प्रभाव डाल सकता है और लाखों भूमिहीन श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों को गरीबी में भेज सकता है।

24. **सिंचाई और कृषि सेवाओं को बहाल करना:** गर्मी और चारे की फसलों, फलों और सब्जियों के निरंतर उत्पादन और खरीफ की बुआई की तैयारी को सक्षम करने के लिए बेहतर ऋण सहित सतही और भूजल आधारित सिंचाई दोनों और कृषि सेवाओं को बढ़ाना।

25. **एनटीएफ़पीएस और लकड़ी-आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला बहाल करना**: गैर-लकड़ी वन उत्पादों और वन-आधारित उत्पादों पर निर्भर वन-निवास और वन-निर्भर आबादी की आजीविका और ऊर्जा सुरक्षा को सक्षम करने, उन्हें गरीबी और निराश्रितता में गिरने से बचाने के लिए।

VI. **गरीबी, आजीविका और सामाजिक संरक्षण**

26. **डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, बढ़ाई गयी पेंशन, आय समर्थन का विस्तार और बेहतर बनाना**: भारत सरकार के के मौद्रिक और राजकोषीय समर्थन नीति और राज्य सरकार के संसाधनों के आधार पर; और प्राथमिकताओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, पेंशन और आय समर्थन योजनाओं का विस्तार करना और बेहतर करना लिए और लगभग वैश्विक बनाने के लिए और सभी गरीब, बुजुर्ग और कमज़ोर परिवारों को शामिल करना।

27. **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका गारंटी कार्यक्रमों का विस्तार और बेहतर बनाना**: परिवर्तित नियमों और भारत सरकार के समर्थन विस्तार के साथ राज्य सरकारों के संसाधनों के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु से मध्यम-अवधि के व्यवधानों को कम करने के लिए आजीविका समर्थन और गारंटी कार्यक्रमों की कवरेज का विस्तार करना।

28. **मज़दूरों और विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों की और उनकी आजीविका की सुरक्षा**: विशेष रूप से प्रवासियों और अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों में, जिसमें आय और आजीविका का समर्थन, किराया और ऋण स्थगन शामिल हैं। श्रम गहन अनौपचारिक आजीविका, सूक्ष्म और एसएमई के लिए विशेष समर्थन पैकेज और उनसे सार्वजनिक और औपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अधिमान्य खरीद। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सभी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए। कानून और व्यवस्था, प्रशासनिक, जीवनरेखा बुनियादी ढांचे और आवश्यक आपूर्ति कार्यों को बनाए रखने वाले अन्य लगभग फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए उचित सुरक्षा और प्रशिक्षण के उपाय।

29. **प्रवासी श्रमिकों और प्रवासी परिवारों की ज़रूरतों को सुरक्षित और संबोधित करना**: गंतव्य और स्रोत (उनके पारगमन के दौरान या अपने घरों में वापस आना) क्षेत्रों में सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका सुरक्षा, आय और ऋण सहायता सहित।

30. **कमज़ोर समूहों की ज़रूरतों की रक्षा करना और उनका पता लगाना**: जैसे कि बेघर, बुजुर्ग, कैदी, मानसिक रूप से विकलांग और डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर और बढ़ी हुई पेंशन, संभव होम डिलीवरी, आपातकालीन भोजन, वस्तु के रूप में सहायता, बेहतर स्वास्थ्य सहायता और चिकिसकीय जांच।

VII. **परिवहन प्रणालियाँ**

31. **रेल, ट्रक, वायु और पोत द्वारा माल परिवहन को बहाल और विस्तारित करना**: भोजन और आवश्यक आपूर्ति, निरंतर प्रक्रिया और रणनीतिक उत्पादन इकाइयों और फिर सभी वाणिज्यिक गतिविधि राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय आवागमन को पहले बहाल करना और फिर बनाए रखना विस्तार करना। यह

रेल या रो-रो रेल सेवाओं जैसे अधिक कुशल, कम कार्बन तरीकों में एक मोडल शिफ्ट को सुविधाजनक बनाने का अवसर हो सकता है।

32. **रेल, बस और नाव के द्वारा राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय यात्री परिवहन बहाल करना**: अंतर-राज्य और अंतर-जिला यात्री परिवहन की चरणबद्ध बहाली, ट्रांसमिशन पैटर्न, जोखिम और कैस लोएड की दैनिक ट्रैकिंग के आधार पर। COVID-19 प्रकोप तक केवल आवश्यक यात्राओं, उचित कीटाणुशोधन, दूरी रखने और निगरानी पर ज़ोर। सार्वजनिक परिवहन में सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत और प्रभावी उपाय एक आदर्श बदलाव को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

33. **शहर के अंदर सार्वजनिक परिवहन (रेल, मेट्रो और बस) की बहाली और विस्तार करना**: COVID-19 प्रकोप नियंत्रित होने तक उचित कीटाणुशोधन, दूरी रखना, निगरानी और केवल आवश्यक यात्राओं पर ज़ोर देने के साथ शहरी, पेरी-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की चरणबद्ध बहाली। सार्वजनिक परिवहन में सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत और प्रभावी उपाय एक आदर्श बदलाव को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

34. **शहर के अंदर निजी परिवहन बहाल करना**: आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने के प्रयास के लिए निजी परिवहन की चरणबद्ध बहाली, लेकिन सार्वजनिक या सक्रिय परिवहन में बदलाव को प्रोत्साहित करके लॉकडाउन अवधि के कुछ वायु प्रदूषण और यातायात दुर्घटना मृत्यु दर को बनाए रखना। साइकिल जैसे सक्रिय परिवहन को प्राथमिकता, जिसके माध्यम से दूरी रखने के मानदंडों को बनाए रखा जा सकता है। यातायात और भीड़ में पोस्ट-लॉकडाउन वृद्धि के लिए पर्याप्त तैयारी।

35. **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री हवाई परिवहन बहाल करना**: भारत सरकार द्वारा जोखिमों के अनुमान पर आधारित बहाली: क्यूंकी COVID-19 का प्रकोप जो अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों द्वारा भारत लाया गया था और भविष्य के संक्रमणों की कई लहरों को देखते हुये। घरेलू उड़ानों में उचित कीटाणुशोधन और दूरी रखने की प्रथाओं के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए प्रभावी जांच, परीक्षण, ट्रेसिंगऔर अलगाव प्रक्रियाएं।

VIII. आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करना और बढ़ाना

36. **आवश्यक सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करना और बढ़ाना**: अंतर्निहित जीवनरक्षक सेवाओं और वितरण और खुदरा श्रृंखलाओं में अनौपचारिक-औपचारिक क्षेत्र की व्यवस्था में बाधाओं को संबोधित करके। प्रमुख हितधारकों के साथ एक संवाद खोलना और लॉकडाउन की स्थिति का मंचन करने और पूर्व-लॉकडाउन रसद श्रृंखलाओं की तेजी से बहाली के लिए बाधाओं को दूर करना। यह उन परिस्थितियों को प्रोत्साहित करने और विनियमित करने का अवसर हो सकता है, जिनके तहत 'गिग इकॉनमी' की आपूर्ति श्रृंखलाएं काम करती हैं और इस क्षेत्र के अपेक्षित विस्तार से पहले रोजगार की बढ़ी हुई सुरक्षा प्रदान करती हैं।

37. **गोदामों और कोल्ड चेन सेवाओं को बहाल करना**: आपूर्तियों के पर्याप्त भंडार और संचालन ट्रैक और सुनिश्चित करने के द्वारा सार्वजनिक, निजी और अनौपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि पीडीएस, अनिवार्य सेवाओं और आर्थिक बहाली को समर्थन दिया जा सके। यह मुख्य सार्वजनिक (जैसे पीडीएस सेवाओं) और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला को तर्कसंगत बनाने और बेहतर बनाने का अवसर हो सकता है।

38. **आवश्यक सामग्री और उत्पादों के उत्पादन का विस्तार करना**: उदाहरण के लिए, दवाओं, चिकित्सा आपूर्ति, भोजन, पका हुआ भोजन, घरेलू आपूर्ति, और अन्य उत्पाद जो लॉकडाउन के दौरान आवश्यक हो गए हैं। यह स्थानीय आर्थिक गतिविधि और रोजगार उत्पन्न करने और प्रणाली का लचीलापन बढ़ाने के लिए स्थानीय या राज्य उत्पादन के लिए आधार हो सकता है। प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह और प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में बुनियादी ढांचे और सेवाओं और कुशल श्रमिकों में सुधार, जुड़ा हुआ स्थानीय आर्थिक विकास और कौशल और उद्यम विकास के माध्यम से सहजीकरण।

IX. निर्माण और आवास

39. **निर्माण और आवास गतिविधि को पुनर्स्थापित और विस्तारित करना**: एक राष्ट्रव्यापी संरचित रोजगार और विकास प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में सार्वजनिक एजेंसियों, रोजगार गारंटी कार्यों, समुदायों और कारीगरों, निजी एजेंसियों और रियल एस्टेट फर्मों द्वारा किए गए आवास और निर्माण गतिविधि का चरणबद्ध पुनर्स्थापन और विस्तार। सभी बेदखली, कार्यकाल सुरक्षा, किराए और ईएमआई स्थिरीकरण और कम आय और प्रवासी परिवारों को किराए के समर्थन पर एक ठहराव।

X. शिक्षा प्रणालियाँ

40. **स्कूल और विश्वविद्यालय के कामकाज को बहाल करना**: केंद्र और राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों) की पूर्ण कार्यप्रणाली की चरणबद्ध बहाली, जिसमें परीक्षाएँ आयोजित करना और प्रवेश संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करना शामिल है।

खंड IV : ट्रांजिशन की तैयारी के लिए बीस मुख्य प्रक्रिया प्रश्नों को संबोधित करना

1. **क्या राज्य लॉकडाउन ट्रांजिशन के लिए कोई चरणबद्ध योजना है जो COVID-19 ट्रांसमिशन और भारत सरकार के नीतिगत मार्गदर्शन को ध्यान में रखती है।** इसका जिला स्तर पर और सेक्टरों में संचालन कैसे किया जाता है? क्या अधिकार, जिम्मेदारी और वित्तीय शक्तियों को पर्याप्त रूप से बांटा गया है?

2. **क्या मध्यम-अवधि (12 - 18 महीने) बहाली की कोई योजना शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है?**

3. **क्या राज्य में कोई वित्तीय, ऋण सहायता और क्रेडिट पैकेज है?** क्या यह केंद्रीय विशेष सहायता, स्थानान्तरण और राज्य योजनाओं और प्राथमिकताओं के साथ योजनाओं को जोड़ता है?

4. **क्या COVID-19 और मूल सेवाओं की प्रदानगी के लिए अन्य स्वास्थ्य कार्यों पर वापस लौटने को संबोधित करने के लिए लॉकडाउन ट्रांजिशन और वित्तपोषण योजनाएं स्वास्थ्य प्रणालियों की उभरती आवश्यकता के साथ तालमेल में हैं?**

5. **क्या कृषि गतिविधि और सेवाओं, रबी की फसल और कृषि और संबद्ध आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त योजना है?** क्या पर्याप्त कृषि कामगारों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित है?

6. **क्या पीडीएस वस्तु के रूप में और सीधे नकद हस्तांतरण प्रणाली के कवरेज का विस्तार करने के लिए तंत्र हैं?** क्या उन्हें लगभग सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है?

7. **क्या सभी बुनियादी सेवाएं कार्य कर रही हैं या फिर तेजी से बढ़ सकती हैं?** क्या इन पर नज़र रखी जा रही है?

8. **क्या चरणबद्ध तरीके से माल परिवहन और यात्री परिवहन का विस्तार करने की योजना है?** क्या यह प्रसारण को रोकने के लिए आकस्मिक योजनाओं के अनुरूप है?

9. **क्या प्रमुख हितधारकों के साथ प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करने की योजना है?**

10. **इन कार्यवाहियों के निष्पादन के लिए कौन से सामान्य / आपातकालीन नियम या प्रशासनिक आदेशों की आवश्यकता है?** उन्हें जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है? निरीक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है?

11. **क्या इन सवालों की जानकारी प्रत्येक जिला नियंत्रण कक्ष में प्रवाहित होती है और प्रत्येक दिन भौतिक या डिजिटल रूप से मैप की जाती है?** क्या राज्य सूचना कक्ष में एकत्रित जानकारी प्रवाहित होती है?

12. **क्या संसाधन प्रवाह की कमी को संबोधित करने के लिए वास्तविक आकस्मिक योजना है?** क्या यह गरीब

और कमज़ोर और दूरस्थ स्थानों को प्राथमिकता देती है? निरीक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है?

13. **क्या कोई आपातकालीन संचार योजना** और नागरिकों, हितधारकों, स्थानीय अधिकारियों, जिला और राज्य परिस्थिति कक्षों से: **आपातकालीन संचार चैनल है।**?

14. **क्या कोई नागरिक और हितधारक आउटरीच तंत्र है?** क्या यह पोस्ट-लॉकडाउन ट्रांजिशन में सहायता करने और स्थानीय और क्षेत्रीय अड़चनों को दूर करने के लिए प्रशासन की सहायता करने के लिए तैयार है?

15. **क्या खाद्य, नागरिक आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन जारी है?** यदि नहीं, तो इन इकाइयों को फिर से कैसे शुरू किया जा सकता है और संवर्धित किया जा सकता है या सीमा पार रसद व्यवस्था की जा सकती है?

16. **वस्तुओं / सेवाओं की अपेक्षित आवश्यकता / मांग कहाँ से आने वाली है?** किस आवृत्ति पर इसे पुनःपूर्ति की आवश्यकता होगी? नोडल संस्थान / जिम्मेदार व्यक्ति कौन है?

17. **आपूर्ति के प्रमुख स्टॉक कहाँ स्थित हैं?** उनकी भरपाई कैसे की जा सकती है? उन्हें कौन नियंत्रित करता है? उनकी आवश्यकता कैसे हो सकती है? बड़े **स्टॉकस** को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है?

18. **आपूर्ति, कर्मियों और परिवहन के लिए भुगतान करने के लिए वित्तीय ज़रूरी संसाधन कहाँ हैं?** उन्हें कौन जारी करेगा? किस आवृत्ति पर? किसके अधिकार के अंतर्गत?

19. **क्या आवश्यक वस्तुओं की कीमतों** और इन कीमतों पर व्यापक रूप से उपलब्ध जानकारी क्या है, **को विनियमित करने और लागू करने के लिए प्रणालियाँ हैं**?

20. क्या सेना और अर्धसैनिक बल की सहायता से **कानून और व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए आकस्मिक योजना है,** अगर नागरिक प्रशासन को उनको शामिल करने की आवश्यकता पड़ जाए तो?

इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स (आईआईएचएस)

इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स (IIHS) एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है जो भारतीय बस्तियों के न्यायसंगत, स्थायी और कुशल परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। आईआईएचएस राष्ट्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक, अर्धसैनिक और नगरपालिका एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों और मानव बस्तियों और शहरीकरण के इंटरफ़ेस पर गैर-लाभकारी सेवाएं भी प्रदान करता है।

आईआईएचएस मिशन का एक मुख्य उद्देश्य भारत के सतत शहरी परिवर्तन में योगदान करना और बड़े पैमाने पर प्रभाव को सक्षम करना है। पिछले 10 वर्षों में, आईआईएचएस ने स्वच्छता, आपदा जोखिम और लचीलेपन (रिजीलियन्स), आवास, ऊर्जा, भूमि शासन और योजना, जलवायु अनुकूलन और शमन जैसे क्षेत्रों में नवाचार और समस्या को हल करने पर बड़े पैमाने पर काम किया है।

आरोमर रेवी

आरोमर रेवी आईआईएचएस के संस्थापक निदेशक हैं। वे आईआईटी-दिल्ली के पूर्व छात्र और दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ एंड मैनेजमेंट स्कूल से हैं। वे एक वैश्विक अभ्यास और विचारशील नेता हैं, और सतत विकास, जोखिम और आपातकालीन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, शासन, सार्वजनिक नीति और वित्त और शहरीकरण में 35 वर्षों के अंतःविषय अनुभव के साथ एक शिक्षक हैं।

iihs®
INDIAN INSTITUTE FOR

IIHS Bengaluru City Campus
197/36, 2nd Main Road, Sadashivanagar, Bengaluru 560 080. India.
T: +91 80 6760 6666 | F: +91 80 2361 6814

IIHS Chennai
Floor 7A, Chaitanya Exotica, 24/51 Venkatnarayana Road, T Nagar Chennai 600 017. India. T: +91 44 6630 5500/6555

IIHS Delhi
803 Surya Kiran, 19 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001. India.
T: +91 11 4360 2798 | F: +91 11 2332 0477

IIHS Mumbai
Flat No.2, Purnima Building, Patel Compound, 20-C, Napean Sea Road, Mumbai 400 006. India. T: +91 22 6525 3874

www.iihs.co.in